सं.ए-45011/4/2020-प्रशा.III

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

****

नई दिल्ली, दिनांकः 24 जनवरी, 2020

कार्यालय ज्ञापन

मुझे आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित दिसम्बर, 2019 माह के दौरान महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के संबंध में मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की प्रति परिचालित करने का निदेश हुआ है।

ह/20 सुरिन्दर पाल सिंह 24.1.2020

(सुरिन्दर पाल सिंह)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

दूरभाषः 23092100

सेवा में,

1. केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
3. मत्रिमंडल सचिव के निजी सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आजाद मार्ग, नई दिल्ली।
6. प्रधानमंत्री के निजी सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
7. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
8. सभी सदस्य, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. राज्य मंत्री (वित्त) के निजी सचिव, वित्त सचिव के प्रधान निजी सचिव, सचिव (आर्थिक कार्य) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (राजस्व) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (व्यय) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (दीपम) के प्रधान निजी सचिव।
11. मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
12. अपर सचिव (श्री ए. गिरिधर), मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
13. डा. सी.एस. महापात्रा, अपर सचिव (एफएसएंडसीएस), आर्थिक कार्य विभाग।
14. श्री के. राजारामन, अपर सचिव (प्रशासन एंड निवेश), आर्थिक कार्य विभाग
15. श्री समीर कुमार खरे, अपर सचिव (एफबी एंड एडीबी), आर्थिक कार्य विभाग।
16. सुश्री मीरा स्वरूप, अपर सचिव और वित्त सलाहकार (वित्त)।
17. श्री संजीव सान्याल, प्रधान आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
18. आर्थिक कार्य विभाग के सभी प्रभागाध्यक्ष।
19. संयुक्त सचिव (बजट)/संयुक्त सचिव (आईपीएफ)/संयुक्त सचिव (एफएम)/संयुक्त सचिव (बीसी एंड आईईआर)/संयुक्त सचिव (निवेश)/सलाहकार (सीएंडसी/एफएसएलआर/एफएसएंडसीएस)/सलाहकार (आईईआर)/सीएए।
20. श्री अरूण कुमार, सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
21. सुश्री राजश्री रे, सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
22. श्री राजेश मल्होत्रा, अपर महानिदेशक (एम एंड सी), वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
23. गार्ड फाइल – 2019

सं. ए-45011/4/2020-प्रशा.III

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

विषयः दिसम्बर, 2019 माह के दौरान आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के संबंध में मासिक सार।

1. **वृहत आर्थिक सिंहावलोकन**

1.1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (नई श्रृंखला-संयुक्त) पर आधारित हैडलाइन मुद्रास्फीति नवम्बर, 2018 में 2.3 प्रतिशत की तुलना में नवम्बर, 2019 में 5.5 प्रतिशत थी। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मूद्रास्फीति नवम्बर, 2018 में 5.4 प्रतिशत की तुलना में नवम्बर, 2019 में 0.58 प्रतिशत रही। अक्तूबर 2019 में औद्योगिक श्रमिकों सीपीआई-आईडब्ल्यू हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के रूप में मुद्रास्फीति अक्तूबर, 2018 में 5.2 प्रतिशत की तुलना में 7.62 प्रतिशत थी। नवम्बर, 2019 में कृषि श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और ग्रामीण श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्रमशः 9.41 प्रतिशत और 9.23 प्रतिशत रही।

1.2 दिसम्बर 2019 में पॉलिसी रेपो दर 5.15 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही। पिछले वर्ष की समान अवधि में 16.2 प्रतिशत की तुलना में नवम्बर, 2019 के अंत में बैंक साख बढ़त 8.0 प्रतिशत हो गई। 21 दिसम्बर, 2018 को 7.26 प्रतिशत की तुलना में 20 दिसम्बर, 2019 को 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल 6.8 प्रतिशत रहा।

1.3 भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) वर्ष 2018-19 की दूसरी तिमाही में 19.0 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 2.9 प्रतिशत) से घटकर वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही में 6.3 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 0.9 प्रतिशत) हो गया तथा यह पिछली तिमाही में 14.3 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 2.0 प्रतिशत) से कम था। प्राथमिक रूप से एक वर्ष पूर्व 50.0 बिलियन अमरीकी डालर के निवल व्यापारिक माल आयात कम होकर 38.1 बिलियन अमरीकी डालर तथा 30.1 बिलियन अमरीकी डालर की अदृश्य प्राप्तियाँ बढकर 31.9 बिलियन अमरीकी डालर होने के कारण वर्षानुवर्ष वाई-ओ-वाई आधार पर चालू खाता घाटा में गिरावट आई। निवल सेवा प्राप्तियाँ समान स्तर (20.0 बिलियन अमरीकी डालर) पर हैं तथा निजी लेनदेन प्राप्तियां, मुख्यतः वे प्राप्तियां जो विदेश में नियुक्त भारतीयों द्वारा विप्रेषित धन का प्रतिनिधित्व करती हैं, 20.2 बिलियन अमरीकी डॉलर पहुंच गई जिसमें वर्ष पूर्व अपने स्तर से 3.5 प्रतिशत की वृद्धि रही। वित्तीय खाते में निवल विदेशी सापेक्ष निवेश 2018-19 की दूसरी तिमाही में 9.6 बिलियन अमरीकी डालर की

तुलना में वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही में 7.4 बिलियन अमरीकी डॉलर था। ऋण और इक्विटी बाजारों दोनों में कुल खरीद के चलते 2018-19 की दूसरी तिमाही में 0.2 बिलियन अमरीकी डालर के अंतर्वाह की तुलना में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही में 2.5 बिलियन अमरीकी डालर का निवल अंतर्वाह दर्ज किया गया। वर्ष पूर्व 2.2 बिलियन अमरीकी डालर के अंतर्वाह की तुलना में वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही में भारत में बाह्य वाणिज्यिक उधारों के कारण निवल अंतर्वाह 3.4 बिलियन अमरीकी डालर रहा। वर्ष 2018-19 की दूसरी तिमाही में, 1.9 बिलियन अमरीकी डालर की कमी की तुलना में विदेशी मुद्रा भंडारों (बीओपी आधार पर) में 2019-20 की दूसरी तिमाही में 5.1 बिलियन अमरीकी डालर की बढ़त रही।

1.4 भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मार्च अंत, 2019 के 411.9 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर से 43.0 बिलियन अमरीकी डालर की बढ़त दर्शाते हुए 20 दिसम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार 454.9 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। नवम्बर, 2019 में 71.5 रुपए प्रति अमरीकी डालर की तुलना में रुपए की औसत मासिक विनिमय दर (संदर्भ दर) दिसम्बर, 2019 माह में 71.2 रुपए प्रति अमरीकी डालर रही।

1.5 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (वर्ष 2011-12 की नई श्रृंखला पर आधारित) द्वारा जारी त्वरित अनुमानों के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में अक्तूबर, 2018 में 8.4 प्रतिशत की बढ़त की तुलना में अक्तूबर, 2019 में (-) 3.8 प्रतिशत की बढत दर्ज की गई। अप्रैल-अक्तूबर, 2019-20 की अवधि हेतु औद्योगिक बढ़त अप्रैल-अक्तूबर, 2018-19 के दौरान हुई 5.7 प्रतिशत की बढ़त की तुलना में 0.5 प्रतिशत थी। आठ मुख्य उद्योगों में नवंबर, 2018 में 3.3 प्रतिशत की तुलना में नवंबर, 2019 में (-) 1.5 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है। मुख्य उद्योगों की बढ़त अप्रैल-नवम्बर, 2018-19 के दौरान 5.1 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-नवम्बर, 2019-20 में 0.0 प्रतिशत रही।

1.6 भारत का व्यापारिक माल निर्यात नवम्बर, 2018 के दौरान 26.1 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना मे 0.3 प्रतिशत की गिरावट दर्शाते हुए नवम्बर, 2019 के दौरान 26.0 बिलियन अमरीकी डालर रहा। भारत का आयात नवम्बर, 2018 में 43.7 बिलियन अमरीकी डालर के आयात मूल्य के स्तर की तुलना में 12.7 प्रतिशत घटकर नवम्बर 2019 के दौरान 38.1 बिलियन अमरीकी डालर था। नवम्बर, 2019 में तेल आयात और गैर-तेल आयात में नवम्बर, 2018 की तुलना में क्रमशः 18.2 प्रतिशत और 10.3 प्रतिशत की गिरावट हुई।

1.7 व्यापार घाटा नवम्बर, 2018 के दौरान 17.6 बिलियन अमरीकी डालर के घाटे की तुलना में नवम्बर, 2019 में 12.1 बिलियन अमरीकी डालर अनुमानित था।

1.8 अक्तूबर, 2019 के दौरान सेवाओं का निर्यात और आयात क्रमश: 17.7 बिलियन अमरीकी डालर और 10.8 बिलियन अमरीकी डालर रहा। अक्तूबर, 2019 के लिए सेवाओं में व्यापार शेष 6.83 बिलियन अमरीकी डालर अनुमानित था।

2. **अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम**

2.1 (क) **(i)** सेबी ने ऋण ईटीएफ/सूचक निधियों हेतु मानदण्ड प्रस्तावित किए हैं जो कि सभी एएमसी द्वारा अपनाया जाना है। मानदण्ड में ऋण सूचक के संघटक, रेटिंग दर, भार आदि निर्धारित किए गए हैं। यह अनुपालन प्रक्रिया भी निर्धारित करता है और सभी विद्यमान ऋण ईटीएफ/सूचक निधियों और उनमें जो कि बाजार में शुरू किए जाने हैं, में लागू होगा।

(ii) आर्थिक कार्य विभाग ने ऋण ईटीएफ की इकाईयों में घरेलू संस्थागत निवेशकों की भागीदारी को सुगम बनाने हेतु 11 दिसम्बर, 2019 की अधिसूचना के द्वारा गैर-सरकारी भविष्य निधियों, अधिवार्षिता निधियों और उपदान निधियों हेतु अपने निवेश दिशानिर्देश मानदण्डों में संशोधन किया है जो कि सेबी द्वारा विनियमित और एएमसी द्वारा प्रबंधित होते हैं जिनकी नियुक्ति विशेष रूप से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई), केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू), केंद्रीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (सीपीएफआई) और अन्य सरकारी संगठनों के बाण्डों में निवेश करने के निमित्त भारत सरकार के साथ किए गए करार के अनुसार की जाती है।

(iii) हाल ही के शीतकालीन सत्र 2019 में संसद के दोनों सत्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकारी बिल-2019 पास किया गया। इसके पश्चात इस विधेयक को 19 दिसम्बर, 2019 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और यह दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित हुआ। इस विधेयक मे भारत में स्थित आईएफएससी में सभी वित्तीय सेवाओं का विनियमन करने हेतु एक एकीकृत प्राधिकार स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

(iv) आर्थिक कार्य विभाग के प्रस्ताव के तदनुरूप उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने कुछ विशिष्ट उत्पादों के भंडारण में छूट देने हेतु महत्वपूर्ण उत्पाद अधिनियम, 1955 के तहत दिनांक 16.12.2019 के राजपत्र अधिसूचना एस.ओ.4471(ई) के माध्यम से एक अधिसूचना जारी की है जिसमें स्टॉक सीमा से व्युत्पन्नों का कारोबार अनुमत है यदि ऐसे उत्पाद विनियम आधारों पर वितरण हेतु उत्पाद व्युत्पन्न विनियमों द्वारा मान्यता प्राप्त वेयरहाउसों में रखे जाते हैं और वेयरहाउस विकास विनियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत हैं।

(ख) **(i)** राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर कार्यदल की पहली बैठक दिनांक 09.09.2019 को हुई और अब तक 28 विभागों/मंत्रालयों के साथ कार्यदल की 20 बैठकें आयोजित की गई जिसमें अवसंरचना विकास, अवसंरचना विकास और निर्माण में लगे कॉरपोरेटों, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं और उद्योग संघों अर्थात सीआईआई, एफआईसीसीआई और एसोचैम के प्रतिनिधि शामिल हैं। माननीय वित्त मंत्री ने 31.12.2019 को एनआईपी पर कार्यदल की रिपोर्ट के संक्षिप्त रूपांतर का अनावरण किया।

(ii) 17.12.2019 को लोक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) की 91वीं बैठक में डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और स्थानांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर ग्वालियर, नागपुर, अमृतसर और साबरमती रेलवे स्टेशनों के विकास हेतु रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई।

(iii) 19.12.2019 को हुई लोक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) की 92वीं बैठक में सवारी गाड़ियों में पीपीपी हेतु रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई।

(ग) **(i)** दिनांक 6.12.2019 को आर्थिक कार्य और केएफडब्ल्यू विकास बैंक के बीच सतत शहरी अवसंरचना विकास चेन्नै स्टार्म वाटर प्रबंधन परियोजना हेतु 150 मिलियन यूरो के ऋण करार और 4 मिलियन यूरो के वित्तपोषण करार पर हस्ताक्षर किए गए।

(ii) 'ऊर्जा दक्षता आवासन कार्यक्रम' परियोजना हेतु दिनांक 12.12.2019 को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और केएफडब्ल्यू विकास बैंक के बीच ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए। कार्यक्रम में शामिल हैं:-

- 277 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण करार (250 मिलियन यूरो के समान अमरीकी डॉलर)
- 10 मिलियन यूरो का अनुदान करार (निवेश अनुदान)
- 1.5 मिलियन यूरो का अनुदान करार (उपायों सहित)

(iii) दिनांक 16.12.2019 को भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरईडीए) और केएफडब्ल्यू विकास बैंक के बीच 222.8 मिलियन अमरीकी डालर (200 मिलियन यूरो के समान) के ऋण करार तथा 1 मिलियन यूरो के साथ उपाय के अनुदान करार पर हस्ताक्षर किए गए।

(iv) दिनांक 19.12.2019 को आर्थिक कार्य विभाग और केएफडब्ल्यू विकास बैंक के बीच "आंध्र प्रदेश जलवायु लोचशील शून्य बजट प्राकृतिक कृषि परियोजना" हेतु 90 मिलियन यूरो के ऋण करार तथा 1 मिलियन यूरो के अनुदान करार पर हस्ताक्षर किए गए।

(v) दिनांक 27.12.2019 को डीईए और एएफडी के बीच कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के 'गैर मोटरयुक्त परिवहन' परियोजना हेतु 27 मिलियन यूरो के उधार सुविधा करार/ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए।

2.2 दिनांक 17.12.2019 को वित्त मंत्री के अनुमोदन से टोगो सरकार को सौर फोटो-वोल्टीय प्रणाली के माध्यम से 350 गांवों के विद्युतीकरण हेतु 40.00 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला का विस्तार किया गया।

2.3 नवम्बर, 2019 तक के व्यय की 2019-20 के बजट अनुमान से तुलना

नवम्बर, 2019 के माह हेतु मासिक लेखे की अनंतिम बिना जांचे गए विवरण के अनुसार नवम्बर, 2019 तक कुल गैर-ऋण प्राप्तियां 10,12,223 करोड़ रुपए थी जोकि पिछले वर्ष के तदनुरूप अवधि (सीओपीपीवाई) में 2018-19 के बजट अनुमान के 49.3 प्रतिशत की तुलना में 2019-20 के बजट अनुमान का 48.6 प्रतिशत है। कुल राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष की उसी अवधि में 50.4 प्रतिशत की तुलना में 2019-20 के बजट अनुमान का 50.1 प्रतिशत है। नवम्बर, 2019 के अंत तक सकल कर राजस्व बजट अनुमान का 47.7 प्रतिशत था (पिछले वर्ष की उसी अवधि में बजट अनुमान का 51.3 प्रतिशत था)। कर राजस्व (निवल) बजट अनुमान का 45.5 प्रतिशत था (पिछले वर्ष की उसी अवधि के 49.4 प्रतिशत) जबकि गैर-राजस्व प्राप्तियां बजट अनुमान का 74.3 प्रतिशत थी (पिछले वर्ष की उसी अवधि में 56.6 प्रतिशत)। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां बजट अनुमान का 24.2 प्रतिशत थी (पिछले वर्ष की उसी अवधि में 28.5 प्रतिशत)। व्यय पक्ष पर, नवम्बर, 2019 के अंत तक कुल व्यय 18,20,057 करोड़ रुपए था जोकि बजट अनुमान का 65.3 प्रतिशत है (पिछले वर्ष की उसी अवधि में 66.1 प्रतिशत)। इसमें बजट अनुमान के 65.6 प्रतिशत का राजस्व व्यय (पिछले वर्ष की उसी अवधि के 66.4 प्रतिशत) और बजट अनुमान के 63.3 प्रतिशत का पूंजीगत व्यय (पिछले वर्ष की उसी अवधि में 63.8 प्रतिशत) शामिल है। ब्याज भुगतान पिछले वर्ष की उसी अवधि में 60.5 प्रतिशत की तुलना में बजट अनुमान का 51.8 प्रतिशत है।

2.4 दिसम्बर, 2019 माह के दौरान निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गईं:-

i. 20 दिसम्बर, 2019 को माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने सुश्री गीता गोपीनाथ, आर्थिक सलाहकार से वार्ता की। सचिव (आर्थिक कार्य) ने भी सुश्री गीता गोपीनाथ के साथ दिसम्बर, 2019 में उनके भारत दौरे के दौरान 19 दिसम्बर, 2019 को बैठक की।

ii. सचिव (आर्थिक कार्य) ने 10 दिसम्बर, 2019 को विश्व बैंक के दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के मुख्य अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की।

iii. सचिव (आर्थिक कार्य) ने 6 दिसम्बर, 2019 को विश्व विकास रिपोर्ट 2020 पर विश्व बैंक के अभ्यावेदन 'वैश्विक मूल्य श्रृंखला के युग में विकास हेतु व्यापार' के नाम से हुई बैठक की अध्यक्षता की।

iv. डॉ. सी.एस. महापात्रा, अपर सचिव (एफएसएंडसीएस) 4 दिसम्बर, 2019 को पेरिस के वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) मानकों के कार्यान्वयन पर स्थायी समिति (एससीएसआई) की एक बैठक में उपस्थित हुए। बैठक की अध्यक्षता लेसेजा गनयागो, साऊथ अफ्रीकन सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने की।

v. सचिव (आर्थिक कार्य) ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग के साथ 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की अर्थव्यवस्था हेतु दिशानिर्देश प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किए।

vi. श्री समीर कुमार खरे, अपर सचिव (एफबीएंडएडीबी) ने दिनांक 18.12.2019 को हुई आर्थिक कार्य विभाग की जांच समिति की 102वीं बैठक की अध्यक्षता की।

vii. श्री समीर **कुमार** खरे, अपर सचिव (एफबीएंडएडीबी) ने विश्व बैंक की ड्राफ्ट रिपोर्ट, "प्लेइंग टू स्ट्रेंथ्सः उत्तर पूर्व भारत को मुख्य धारा में लाने हेतु नीति प्रारूप" पर चर्चा करने हेतु दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को नई दिल्ली में हुई बैठक की अध्यक्षता की।

viii. श्री समीर **कुमार** खरे, अपर सचिव (एफबीएंडएडीबी) ने विश्व बैंक की ड्राफ्ट रिपोर्ट "प्लेइंग टू स्ट्रेंथ्सः उत्तर पूर्व भारत को मुख्य धारा में लाने हेतु नीति प्रारूप" पर चर्चा करने हेतु दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 को हुई बैठक की अध्यक्षता की।

ix. अपर सचिव (एफबीएंडएडीबी) ने 4-6 दिसम्बर, 2019 को भोपाल में विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की त्रि-पक्षीय पोर्टफोलियो समीक्षा (टीपीआरएम) की अध्यक्षता की।

x. 19 दिसम्बर, 2019 को द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) पर चर्चा करने हेतु रूस के साथ डिजीटल वीडियो कांफ्रेस (डीवीसी) की गई।

xi. 31.12.2019 को एनआईआईएफ ट्रस्टी लिमिटेड के बोर्ड की बैठक हुई।

3. **न्यूनतम सरकार, अधिकतम अभिशासन**

विशेषकर, सूचना के प्रस्तुतीकरण में आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

4. **एसीसी के निर्देशों/आदेशों का पालन न किया जाना**

शून्य।

5. **माह के दौरान स्वीकृत किए गए एफडीआई प्रस्ताव और विभाग में अनुमोदन हेतु लंबित एफडीआई प्रस्तावों की स्थिति**

विभाग में अनुमोदन हेतु लंबितः 05

****